एसोसिएशन के सम्बन्ध में 24 जुलाई, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1051 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आर्किटेक्चर ट्रेड में लगे व्यक्तियों से डिग्री स्तर पर ट्रेड परीक्षा लेने का था ;

(ख) यदि हां, तो आर्किटेक्चर और रीजनल प्लानिंग सम्बधी अखिल भारतीय तकनीकी अध्ययन बोर्ड द्वारा 4 दिसम्बर, 1972 को लिए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ;

(ग) क्या सरकार को इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ आर्किटेक्ट की ओर से अनावश्यक विलम्ब करने से हुई हानि के बारे में जानकारी है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार ने इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ आर्किटेक्ट से वास्तुशिल्पीय कार्मिकों के लाभ के लिए डिग्री स्तर पर वास्तुशिल्प में व्यावसायिक परीक्षा यथा सम्भव शीघ्र आयोजित करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ). स्थिति का पता लगाने के लिए संस्थान से पूछताछ की जा रही है और जो भी सूचना प्राप्त होगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय ऊन उत्पादन तथा विपणन योजना

4565. **श्री छविराम वर्मा** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम कार्यालय जो केन्द्रीय ऊन उत्पादन तथा विपणन योजनाकार्य को समन्वित करने में सहायता करता था देश के आठ राज्यों में ऊन के क्रय-विक्रय का प्रबन्ध करता था, विश्व बैंक द्वारा सहायता बन्द कर दिये जाने के कारण बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र द्वारा करोड़ों रुपये की राशि व्यय की गई है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में 10 लाख भेड़ें हैं जिनसे 570 टन ऊन प्राप्त होती है तथा राजस्थान से 500 टन ऊन प्राप्त होती है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त योजना के अन्तर्गत उचित वर्गीकरण तथा विपणन प्रबन्धों में सहायता देने तथा भेड़ पालकों के लाभ के लिये उक्त कार्यालय को मध्य प्रदेश और राजस्थान में खोलने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ किए गए करार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के कार्यालय ने 1974 में यह कार्यक्रम बंद कर दिया।

(ख) इस योजना पर 2.95 करोड़ रुपया व्यय किया था।

(ग) जी, हां।

(घ) ऊन का उचित श्रेणीकरण तथा विपणन करने व भेड़ पालकों की सहायता करने के लिये भारत सरकार का विभिन्न राज्यों में ऊन बोर्डों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार का एक बोर्ड राजस्थान में पहले से चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना का कोई लाभ नहीं उठाया है।

पुनर्वास कालोनियों में डी० डी० ए० के फ्लैट

4566. **श्री लालजी भाई :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कम मूल्य पर लोगों को फ्लैट देने के लिए पुनर्वास कालोनियों में फ्लैटों का निर्माण किया था तथा क्या यह सभी फ्लैट ग्राहकों के अभाव में अभी भी खाली पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 4583 टेनामेण्टों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था जिनमें से 4066 टेनामेण्ट पूर्ण हो गए थे। 1488 टेनामेण्ट पहले ही आबंटित किए जा चुके हैं तथा शेष टेनामेण्ट खरीददारों की कमी के कारण खाली पड़े हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

तकनीकी संस्थान की स्थापना करना

4567. **श्री हया राम शाक्य :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार की ओर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि मण्डल फरवरी/मार्च, 1978 में तकनीकी संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में ईरान गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति लिए बगैर ही ईरान सरकार के प्राधिकारियों के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये थे और वहां से लौटने के बाद भी इस बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई थी और अब ईरान सरकार उपरोक्त करार के कार्यान्वयन के लिए जोर डाल रही है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस मामले में जांच कराने और दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग), प्रश्न नहीं उठता।